vinetur

ईयू की कृषि समिति ने वाइन और मांस के प्रचार के लिए सहायता का समर्थन किया

सांसदों ने इस महीने के अंत में पूरी संसद में प्रस्ताव पर विचार से पहले कम-से-कम 2026 के स्तर पर वित्तपोषण की मांग की।

शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026



यूरोपीय संघ अपने अगले वार्षिक कार्यक्रम पर बहस कर रहा है और यूरोपीय संसद की कृषि समिति ने ऐसी रिपोर्ट का समर्थन किया है जिसमें स्थिर वित्तपोषण तथा वाइन और मांस के लिए निरंतर सहायता की मांग की गई है। इस बीच, यूरोपीय सांसद संघ की कृषि उत्पाद प्रचार नीति को मजबूत करने का दबाव बना रहे हैं।

Agra Europe के अनुसार, Comagri के नाम से जानी जाने वाली समिति ने 5 अक्टूबर को स्ट्रासबर्ग में 37 मतों के पक्ष और 7 मतों के विरोध से इस पहल संबंधी रिपोर्ट को मंजूरी दी ; 1 सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अब यह प्रस्ताव पूरी संसद के पास जाएगा। उम्मीद है कि सदन के अक्टूबर के दूसरे पूर्ण सत्र में इस पर विचार होगा, जो 19 से 22 अक्टूबर तक निर्धारित है।

समिति के रुख का मुख्य आधार ईयू के प्रचार-विपणन वित्तपोषण को कम-से-कम 2026 के स्तर पर बनाए रखने की मांग है। सांसदों ने वित्तपोषण तक पहुंच आसान करने और आवेदकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल बनाने की भी मांग की। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बाजार की स्थितियां बदलने या भू-राजनीतिक घटनाओं से मूल योजनाएं बाधित होने पर स्वीकृत अभियानों में उत्पादों, वित्तपोषण या लक्षित बाजारों को बदलने की अधिक गुंजाइश होनी चाहिए। समिति ने तथाकथित बहु-कार्यक्रमों के लिए अधिक धन देने का सुझाव भी दिया, जिनमें एक से अधिक सदस्य देशों के भागीदार शामिल होते हैं।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब ईयू 2027 के वार्षिक प्रचार कार्यक्रम पर चर्चा कर रहा है और कृषि संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगले साल वित्तपोषण में भारी गिरावट आ सकती है। Agra Europe की रिपोर्ट के अनुसार, 7 अक्टूबर को प्रचार नीति को समर्पित विशेषज्ञ समिति की बैठक के एजेंडे में भी यह मुद्दा शामिल था।

सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों में से एक यह था कि क्या वाइन और मांस को प्रचार कार्यक्रम के तहत पात्र बनाए रखा जाना चाहिए। कृषि समिति के सदस्यों ने कहा कि दोनों क्षेत्रों को पात्र बने रहना चाहिए। इस विषय पर रिपोर्टर की भूमिका निभा रहे यूरोपीय पीपुल्स पार्टी के इतालवी सांसद Salvatore De Meo ने कहा कि समिति ने मांस और वाइन समेत सभी पात्र कृषि क्षेत्रों और उत्पादों के साथ बिना भेदभाव समान व्यवहार की पैरवी की है।

पेय उद्योग इस रुख पर करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि उत्पादों की पात्रता और बजट का स्तर मिलकर यह तय कर सकते हैं कि वाइन उत्पादकों को विदेशी बाजारों में अपनी स्थिति बचाने या मजबूत करने के अभियानों के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण मिलता रहेगा या नहीं। भविष्य के कार्यक्रमों में पात्रता नियमों या वित्तपोषण में से किसी को भी सख्त किया गया, तो पेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों के लिए निर्यात प्रचार हेतु धन हासिल करना अधिक कठिन हो सकता है।

ब्रसेल्स में कृषि क्षेत्र के हितधारकों ने समिति के मतदान का स्वागत किया। उनका मानना है कि यह यूरोपीय आयोग को कार्यक्रम कमजोर न करने का संकेत देता है। 6 अक्टूबर को जारी बयान में कृषि नीति समूह Farm Europe और Eat Europe ने कहा कि संसद की रिपोर्ट ने पर्याप्त बजट के पक्ष में स्पष्ट संदेश दिया है। उनका तर्क था कि यदि ईयू अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और वैश्विक बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ स्थिर और पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी होने चाहिए।

कृषि संगठनों और सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ईयू के मुख्य कृषि लॉबी समूह Copa-Cogeca ने भी समिति के रुख का समर्थन किया और ध्यान राष्ट्रीय सरकारों की ओर दिलाया। समूह ने कहा कि 2027 के ईयू बजट के मसौदे में संशोधन पत्र पर मतदान के दौरान सदस्य देशों को भी उतनी ही महत्वाकांक्षा दिखानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रचार कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

प्रचार नीति पर बहस बजट के आकार तक सीमित नहीं है। बदलाव के समर्थकों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था अस्थिर बाजारों में काम कर रही कंपनियों और उत्पादक समूहों के लिए जरूरत से ज्यादा कठोर हो सकती है। किसी एक गंतव्य के लिए बनाया गया अभियान व्यापार की स्थितियां बदलने, उपभोक्ता मांग में फेरबदल या भू-राजनीतिक तनाव से किसी बाजार पर असर पड़ने पर जल्द ही अप्रासंगिक हो सकता है। मंजूरी के बाद अधिक लचीलापन देने की मांग करके सांसद

ऐसे क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी सफलता समय पर लिए गए विपणन निर्णयों पर निर्भर करती है।

संसद की पहल संबंधी रिपोर्ट अपने आप में अंतिम वार्षिक बजट तय नहीं करती, लेकिन आयोग और सदस्य देशों के 2027 के कार्यक्रम पर काम करने के दौरान राजनीतिक दबाव बढ़ाती है। पूरी संसद में होने वाले आगामी मतदान से पता चलेगा कि कृषि समिति के रुख को व्यापक समर्थन हासिल है या नहीं—खासकर पात्र उत्पादों की सूची में वाइन को बनाए रखने और खर्च मौजूदा स्तर पर रखने के सवाल पर।